

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 17 अक्टूबर 2026 वर्ष-9,अंक-256 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com



www.facebook.com/krantisamay1



www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त

समाचार

महाराष्ट्र में पटाखे पूरे साल बैन, बनाने-बेचने पर रोक नहीं

मुंबई (एजेंसी)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर लगी रोक पूरे साल लागू कर दी। यह रोक नवरात्रि, दीवाली, क्रिसमस और अन्य सभी त्योहारों पर लागू होगी। आदेश



पूरे महाराष्ट्र में त्योहारों के जुलूसों के दौरान शोर और वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिया गया है। जस्टिस गिरिश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोकले की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। बेंच ने कहा,जब तक नागरिक हालात की जरूरत को नहीं समझेंगे और शहरों में रहने के लंबे समय के खतरों के प्रति जागरुक नहीं होंगे, तब तक हालात बिगड़ते रहेंगे। ऐसे शहर गैस चैंबर में बदल सकते हैं।

टिवशा डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में ट्रायल रोका

एमपी हाईकोर्ट में सास गिरिबाला की जमानत पर अब 26 अक्टूबर को सुनवाई



भोपाल (एजेंसी)। भोपाल के चर्चित दिवशा शर्मा डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के सेशन कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर विपक्षी पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। शीर्ष अदालत ने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई, लिप्चा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने यह आदेश लिप्चा के पिता नवनीध शर्मा की याचिका पर दिया।



मां स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। वे अपने पुत्र को गोद में धारण करती हैं और कमल पर विराजमान रहती हैं। उनकी पूजा मातृत्व, प्रेम, करुणा और वात्सल्य का संदेश देती है। भवत संतान की सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और जीवन में शांति के लिए उनकी आराधना करते हैं।

गाजियाबाद में सीएम योगी का सपा पर हमला,कहा इन्होंने गिरगिट की तरह बदला रंग,टिकट बेचने का किया काम

गाजियाबाद (एजेंसी)। गाजियाबाद में आयोजित शिक्षक-स्नातक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को डासना स्थित सुंदरदीप कॉलेज में

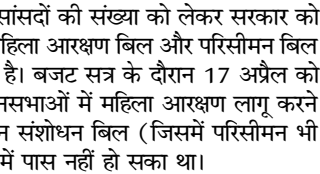
विधान परिषद चुनाव के मतदाताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उसके शासनकाल में दंगों, कर्फ्यू और बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में सुरक्षा, धार्मिक आयोजनों, बुनियादी ढांचे और शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों का जिक्र किया।

संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की है तैयारी!

मोदी सरकार इसी महीने बुला सकती है सत्र, विरोध में है विपक्ष

लोकसभा सीटें बढ़ाने और परिसीमनबिल पेश करने का अनुमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर जारी विरोध के बीच सरकार इस महीने के अखिर में संसद का एक विशेष सत्र बुला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद के इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे की वजह परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिलों को फिर से संसद के सामने पेश करके पास करना है। सदन में मौजूद सांसदों की संख्या को लेकर सरकार को पूरा भरोसा है कि इस बार महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को पास कराया जा सकता है। बजट सत्र के दौरान 17 अप्रैल को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने के लिए लाया गया संविधान संशोधन बिल (जिसमें परिसीमन भी शामिल था) निचले सदन में पास नहीं हो सका था।



बिल पास कराने के

लिए सरकार का नंबर गेम

संविधान संशोधन के लिए संसद में बहुमत की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि दोनों सदनों में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होना चाहिए। सरकार को ये बिल पास कराने के लिए 360 सीटों की जरूरत है। लोकसभा की मौजूदा संख्या 540 है। तृणमूल और शिवसेना के सांसदों के सत्ता पक्ष में शामिल होने से इस बार सदन में स्थिति बदल सकती है। मौजूदा संसद में एनडीए के पास बहुमत तो है, लेकिन उनके पास वह जादुई आंकड़ा (दो-तिहाई बहुमत) नहीं है। हालांकि, पिछले सत्र के मुकाबले सरकार की स्थिति बेहतर हुई है। तृणमूल के 20 सांसद और शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसद सत्ता पक्ष में शामिल हो गए हैं।

11 दिसंबर को कनाडा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

ट्रेड डील पर होगी बातचीत,कारोबार बढ़ाने के नियम तय होंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से 12 दिसंबर को कनाडा के दौर पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत होगी। भारत-कनाडा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना भी है। इसके तहत दो देश व्यापार, निवेश और कारोबार बढ़ाने के लिए नियम तय करते हैं। भारत और कनाडा 2030 तक आपसी कारोबार को बढ़ाकर सालाना 7 लाख करोड़ रुपए करना चाहते हैं।



पीएम मोदी ने मार्क कार्नी से फोन पर बात की थी

प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच 13 अक्टूबर को फोन पर बातचीत हुई। मोदी ने इसे अच्छी बातचीत बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई।

घर से निकलते ही दीपके गिरफ्तार

तिरंगा मार्च के लिए कर्नाट प्लेस पर जा रहे थे सीजेपी चीफ

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने तिरंगा यात्रा के लिए निकले अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसके लिए दीपके व अन्य सीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। 6 दिनों में दीपके को दूसरी बार कस्टडी में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया गया था, अगले दिन छोड़ दिया गया। नई दिल्ली जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू है। यानी 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस इंडेवलाइन स्थित उस बंगले पर पहुंची थी, जहां सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ठहरे हुए थे। पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन नहीं करने का नोटिस दिया था। इस दौरान दीपके की



पुलिस से बहस हो गई थी। उन्होंने पुलिस से कहा कि यह कोई रैली या प्रोटेस्ट नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तिरंगे के सम्मान और देश के गौरव को बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि हमारे तिरंगे को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए और

देशभक्ति हर व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। साथ ही, दिल्ली पुलिस ने संदेश दिया, तिरंगे का सम्मान करें और देश का गौरव बनाए रखें। दिल्ली के कर्नाट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में सीजेपी के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हलचल तेज हो गई थी।

‘सुदर्शन सेतु’ के बाद अब ‘बेट-द्वारका कॉरिडोर’ पर फोकस

गुजरात सरकार का मास्टरप्लान तैयार, इको-टूरिज्म केंद्र बनाने की योजना

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात सरकार ने बेट द्वारका कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार ने विश्व स्तरीय आध्यात्मिक और इको-टूरिज्म केंद्र में बदलने के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना शुरू की है। गुजरात में काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर काम करने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य उन लाखों तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को आधुनिक बनाना है, जो द्वारका आते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रद्धालुओं



की बढ़ती संख्या को देखते हुए, राज्य के राजस्व विभाग ने 31 सर्वे नंबरों के अंतर्गत एक हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण करने के लिए एक

आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। द्वारका के डिटी कलेक्टर की भूमि खाली कराने और कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पहले बनाया गया

सुदर्शन सेतु

द्वारका कॉरिडोर प्रोजेक्ट हाल ही में उद्घाटन किए गए सुदर्शन सेतु के बाद शुरू किया गया है। यह भारत का सबसे लंबा केबल-स्टे ब्रिज है, जो ओखा (मुख्य भूमि) को बेट द्वारका से जोड़ता है। केबल-स्टे ब्रिज को करीब 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इस पुल के फुटपाथों को श्रीमद्भगवतगीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण के चित्रों से सजाया गया है। इस पुल का इस्तेमाल हर मीन में 24 घंटे किया जा सकता है।

पहला देसी बहुउद्देशीय पोत ‘समर्थक’ नौसेना में शामिल

स्वदेशी हथियारों से लैस यह पोत करेगा समुद्र की निगहबानी

करवार (एजेंसी)। भारत की निजी पोत निर्माण कंपनी द्वारा निर्मित पहले बहुउद्देशीय पोत समर्थक को शुक्रवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसे युद्धपोत निर्माण में घरेलू उद्योग की भूमिका बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। करवार स्थित नौसैन्य अड्डे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि पोत का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने तमिलनाडु के कट्टूपल्ली स्थित अपने पोत निर्माण केंद्र किया है और इस पोत में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस अवसर पर कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड भी मौजूद थे।



सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणी कर फंस गए संजय राउत

थमाया नोटिस,सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार से भी जवाब मांगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत से सीजेआई सूर्यकांत पर टिप्पणियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। राउत ने चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया ब्लाक के नेताओं से मिलने से इनकार करने पर सीजेआई की आलोचना की थी। पत्रकार निखिल वागले को भी नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को आपराधिक अवमानना याचिका पर हुई है। कोर्ट ने कहा कि संस्थानों पर हमले अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दोनों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की

कार्रवाई क्यों न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय राउत और निखिल वागले को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी है। बेंच पहले उनके जवाब पर विचार करेगी। यह विवाद सीजेआई सूर्यकांत के इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का अनुरोध टुकड़ाने के बाद शुरू हुआ था। सीजेआई ने कहा था कि मामला याचिका के जरिए अदालत में उठाना जा सकता है। संजय राउत और निखिल वागले ने सीजेआई के इस फैसले की आलोचना की थी। 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था।

आम आदमी की थाली पर महंगाई का सर्जिकल स्ट्राइक 2026!

(लेखक-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी)

महंगी थाली, जेब खाली और जनता परेशान! खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत और थोक महंगाई 11.39 प्रतिशत में बढ़ाई सरकार की धड़कनें ; सरकार की अग्निपरीक्षा! क्या 2027 के चुनावों में जनता वोट से दंगी जवाब? – समग्र व्यापक महा-विश्लेषण

शक्कर, तेल, प्याज, दाल चावल लहसुन अदरक नींबू और ईंधन की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जेब पर दोहरी मार ; के बीच सरकार, आरबीआई औरअर्थव्यवस्था के सामने कठिन परीक्षा!

महंगाई पर कानूनों की कसौटी जमाखोरी पर कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 फिर भी महंगाई से हाहाकार ! –बड़ा सवाल-आम उपभोक्ता को राहत कब?

वैश्विक स्तरपर महंगाई जब केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित रहती है,थाली महंगी,बचत पर संकट और मध्यमवर्ग की बढ़ती बेचैनी,तब उसका प्रभाव बाजार की रिपोर्टों और सरकारी दस्तावेजों में दिखाई देता है,लेकिन जब वही महंगाई रसोई की चौखट पार करके आम आदमी की थाली, परिवार के मासिक बजट, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च और आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौती बन जाती है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र, बताना चाहूंगा कि भारत में14 अक्टूबर को सामने आए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई दर के 11.39 प्रतिशत तक पहुंचने के दावे, सितंबर 2026 की महंगाई से जुड़े आंकड़ों ने इसी गंभीर परिस्थिति की ओर संकेत किया है। इसके पूर्व 13 अक्टूबर को जारी खुदरा महंगाई के आंकड़ों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर बढ़कर 5.54 प्रतिशत पहुंचने और अभी थोक मूल्य सूचकांक ने आर्थिक बहस को तेज कर दिया है। यदि इन आंकड़ों की पुष्टि आधिकारिक मूल विज्ञप्तियों से होती है, तो यह स्थिति

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), उद्योग जगत और करोड़ों घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गंभीर चिंता का विषय होगी।सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रसोई का खर्च लगातार बढ़ने लगे, तो आम परिवार अपनी जरूरतों, इच्छाओं और बचत के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाए?

साथियों बात अगर हम रसोई के बजट पर महंगाई का सीधा हमला- इसको समझने की करें तो,शक्कर दालों से लेकर व प्याज से लेकर नींबू तक बढ़ती परेशानी भारतीय परिवारों के लिए रसोई केवल भोजन तैयार करने की जगह नहीं,बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दाल, चावल, आटा, प्याज, आलू, लहसुन,अदरक, नींबू और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का असर लगभग हर आय वर्ग पर पड़ता है।विशेष रूप से निम्न आय वर्ग और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खाद्य पदार्थों की महंगाई अधिक कष्टकारी होती है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च होता है। प्याज की कीमतों में असामान्य वृद्धि की खबरें, लहसुन और अदरक के महंगे होते भाव तथा नींबू जैसी सामान्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें घरेलू बजट को असंतुलित कर सकती हैं। शक्कर का खुदरा मूल्य 65 रुपये प्रति किलोग्राम बताए जाने का दावा भीउपभोक्ताओं की चिंता बढ़ाता है, हालांकि वास्तविक बाजार भाव शहर, गुणवत्ता और बिक्री केंद्र के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।महंगाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि परिवारों को समान आय में पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं।। कोई परिवार फल खरीदना कम करता है,कोई दूध और

पोष्टिक खाद्य पदार्थों की मात्रा घटाता है, तो कोई मनोरंजन, कपड़े और अन्य जरूरी खर्चों में कटौती करता है। इस प्रकार महंगाई केवल जेब खाली नहीं करती, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और परिवार की आर्थिक सुरक्षा को भी सटीकता से प्रभावित करती है।

साथियों बात अगर हम खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत , थोक महंगाई 11.39 प्रतिशत- अर्थव्यवस्था के लिए

खतरे की घंटी? इसको समझने की करें तो, महंगाई के इन दोनों आंकड़ों को समझना आवश्यक है। खुदरा महंगाई बताती है कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितनी बढ़ली हैं। दूसरी ओर, थोक महंगाई उत्पादकों और थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलाव का संकेत देती है।सरकारीआंकड़ों के अनुसार,सितंबर 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 5.54 प्रतिशत और थोक महंगाई बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई, जबकि अगस्त में ये क्रमशः4.83 प्रतिशत और 9.92 प्रतिशत थीं। खुदरा महंगाई के आधिकारिक आंकड़े 12 अक्टूबर को जारी हुए और थोक महंगाई के आंकड़े 14 अक्टूबर को सामने आए। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि 11.39 प्रतिशत थोक महंगाई का अर्थ यह नहीं है कि बाजार की प्रत्येक वस्तु 11.39 प्रतिशत महंगी हो गई है। इसका अर्थ है कि थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं के समग्र मूल्य स्तर में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इतनी वृद्धि दर्ज हुई है। फिर भी, थोक महंगाई का लगातार ऊंचा रहना चिंता बढ़ाता है, क्योंकि इससे कंपनियों की उत्पादन लागत, परिवहन खर्च और व्यापारिक गतिविधियों पर दबाव पड़ सकता है। यदि कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं, तो आने वाले महीनों में खुदरा बाजार में भी महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।

साथियों बात अगर हम ईंधन और कच्चे तेल का झटका महंगाई की आग में घी इसको समझने की करें तोसितंबर के थोक महंगाई आंकड़ों में सबसे चिंताजनक पहलुओं में ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है। ईंधन एवं बिजली समूह की महंगाई अगस्त के 22.93 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 25.85 प्रतिशत पहुंच गई।। प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई 8.67 प्रतिशत और विनिर्मित उत्पादों की महंगाई 9.76 प्रतिशत दर्ज की गई। थोक खाद्य सूचकांक भी अगस्त के 7.05 प्रतिशत से बढ़कर 8.66 प्रतिशत हो गया। कच्चे तेल और

गरीबी मुक्त भारत : सपनों से संकल्प तक

(लेखक- सुनील कुमार महला)

(17 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पर विशेष आलेख)।

गरीबी, भूखमरी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रविर्ष 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यहां इस आलेख में सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर गरीबी से तात्पर्य या मतलब क्या है? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि गरीबी वह स्थिति है, जिसमें कोई व्यक्ति या परिवार भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि यह सम्मानजनक जीवन जीने, समान अवसर पाने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। यहां निष्कर्ष के तौर पर यह बात कही जा सकती है कि गरीबी केवल धन का अभाव नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं, अवसरों, अधिकारों और सम्मानजनक जीवन से वंचित होने की स्थिति भी है। वास्तव में सच तो यह है कि गरीबी का प्रभाव व्यक्ति के साथ-साथ उसके परिवार, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है।

देश और समाज के लिए गंभीर चुनौती- गरीबी -

बहरहाल, यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि गरीबी, भूखमरी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार आज भी हमारे समाज में विद्यमान गंभीर चुनौतियाँ हैं। गरीबी के कारण लाखों लोग भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। वहीं पर भूखमरी और कुपोषण बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि आर्थिक और सामाजिक असमानता अवसरों तक समान पहुँच में बाधा बनती है। सामाजिक बहिष्कार के कारण वंचित वर्ग के लोग समाज की मुख्यधारा से दूर रह जाते हैं। वास्तव में, इन समस्याओं का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि समान अवसर, सामाजिक न्याय, जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। एक समतामूलक समाज वही है, जहाँ किसी व्यक्ति की पहचान उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा और मानवीय गरिमा से हो। विश्व और भारत में



गरीबी आज भी एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौती है। आंकड़ों की बात करें तो विश्व बैंक के सितंबर 2026 के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2024 में दुनिया के लगभग 82.43 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रहे थे। भारत में विश्व बैंक की 3 डॉजर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय गरीबी-रेखा के आधार पर वर्ष 2022–23 में अत्यधिक गरीबी की दर 5.3 प्रतिशत थी। वहीं, नीति आयोग के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी की दर 2022–23 में अनुमानतः 11.28 प्रतिशत रही। ये आँकड़े गरीबी में आई कमी को दर्शाते हैं, लेकिन भोजन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के समान अवसर सुनिश्चित करने की चुनौती अब भी बनी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। यहां पाठकों को बताता चूँ कि (नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार) वर्ष 2013–14 से 2022–23 के दौरान भारत में लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। इस अवधि में बहुआयामी गरीबी की दर 29.17 प्रतिशत से घटकर 11.28 प्रतिशत रह गई।

सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रमुख प्रयास—

हाल फिलहाल यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार खाद्य सुरक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर एक साथ काम कर रही है और यही कारण भी है कि हमारे देश में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। गौरतलब है कि आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों की भोजन संबंधी जरूरतों और घरेलू खर्च का बोझ कम करने में मदद मिल रही है और इस योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 31 दिसंबर 2028 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को क़ाब पत्र उपलब्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं और एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2029 तक कुल 4.95 करोड़ घर उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अलावा, ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका उपलब्ध करने के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा दिसंबर 2025 में जारी

सरकारी विवरण में विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वर्ष 125 दिन तक रोजगार की गारंटी का उल्लेख है। इतना ही नहीं, आज दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर बचत, बैंक ऋण, स्वरोजगार और छोटे उद्यमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य परिवारों की नियमित आय बढ़ाना है। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को अस्पताल में उपचार के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे बीमारी के कारण परिवारों पर पड़ने वाले भारी आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलती है।। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने तो गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराकर स्वच्छ ईंधन तक पहुँच बनाकर रसोई की तत्वीर तक बदल दी है और इस योजना के कारण आज 10.5 करोड़ से ज्यादा घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुँच चुका है। वहीं पर विभिन्न बुनियादी सुविधाएं जैसे कि जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण सड़क निर्माण, बिजली और सामाजिक सुरक्षा जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, यह काबिले-तारीफ है। आज देश में कोशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है तथा इस क्रम में आज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना तथा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से युवाओं को रोजगार योग्य कौशल, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।

अंत में यही कहूंगा कि गरीबी उन्मूलन के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त रोजगार, खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना आवश्यक है ; सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाकर तथा स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, और सरकार व समाज के संयुक्त प्रयासों से ही गरीबी, भूखमरी और असमानता को कम कर एक समतामूलक समाज का निर्माण संभव है।

(सुनील कुमार महला, फ़ीलांस राइटर, कॉलिमिस्ट व युवा साहित्यकार।)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

भक्त के भीतर रहते हैं कृष्ण

जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे।

तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली और विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी-कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले-भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े-बड़े विद्वान पुरुष हैं, जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं।अतः कृष्णभावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञानरहित भी हो सकते। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्णभावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे।

आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त

नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है— जो लोग शुद्धभक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हों तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हों, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं। भगवान अजरुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है।

भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे।परम सत्य, कृष्ण, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं।शुद्धभक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सृष्टि के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है।

लोकतंत्र की लड़ाई में सरकार को बड़ी चुनौती, 1975 जैसे हालात

(लेखक-सनत जैन)

भारत में एक बार फिर 1975 जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सरकार के खिलाफ हर वह वर्ग सामने खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जो इस तरह के आंदोलन में कभी शामिल नहीं होता। सारे देश में जितने भी विपक्षी दल हैं इस समय सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उसमें विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहकर सनसनी मचा दी है, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में सभी लोग शामिल हों। कॉर्पोरेट जनता पार्टी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें सभी विपक्षी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, अधिवक्ता यहां तक बिना

काउंसिल के अधिवक्ता भी इस आंदोलन में शामिल हों। दिल्ली के प्रेस क्लब में कॉर्पोरेट जनता पार्टी के संस्थापक अभिषेक दीपक के पत्रकार-वार्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, दक्षिण के अभिनेता प्रकाश राज, छात्र नेता नेहा बोरा जब संबोधित कर रहे थे उसी समय कुछ लोगों ने पत्रकार वार्ता में व्यवधान पैदा किया। उसके बाद प्रशांत भूषण उत्तेजित हो गए और उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में अब सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के शामिल होना होगा। यह लड़ाई अब युवाओं के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। किसी भी विचारधारा या कोई मतभेद अब इस लड़ाई में बाधा नहीं बनेंगे। सरकार और पुलिस की बर्बरता को सहन नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव

आयोग द्वारा जो गड़बड़ी की गई है उसे रोकने और सही करने के साथ-साथ वॉलेट पेपर से चुनाव करने और ईटीएम का बहिष्कार करने का आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार को हटाने के लिए यह आंदोलन करेंगे। सरकार से हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। लोकतंत्र की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अब सभी को एकजुट होकर सड़कों पर आना पड़ेगा।

इसी तरह की स्थिति 1975 में जयप्रकाश आंदोलन में बनी थी। उस समय महंगाई,

सुनापाखोरी और इंदिरा गांधी द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे थे उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। देखते ही देखते यह आंदोलन सारे देश में फैल गया था। 1975 में भी इसकी अगुवाई छात्रों ने की थी। 1975 के आंदोलन में सभी विपक्षी दल, सभी ट्रेड यूनियन, सभी छात्र यूनियन, एकजुट होकर आंदोलन शुरू किया था। इसी समय इलाहाबाद हाइकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया था। उसके बाद स्थितियां बड़ी तेजी के साथ बदलीं, इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। तब जाकर स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सका था। कुछ इसी तरह की स्थिति अब 50 साल बाद एक बार फिर बनती हुई दिख रही है। जिस तरह से चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जो आंदोलन शुरू हुआ था अब वह आंदोलन बड़ी तेजी के साथ सभी वर्गों के बीच में फैलता चला जा रहा है। विशेष रूप से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी अब

खुलकर सामने आ गए हैं। वह भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा यह भी आह्वान किया गया है कि जब लोकतंत्र खतरे में हो ऐसी स्थिति में बार काउंसिल को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इस लड़ाई में वकील भी शामिल हों अन्यथा लोकतंत्र को बचा पाना संभव नहीं होगा। जिस तरह से सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, सामाजिक संगठन भी इन आंदोलन और प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। यह आंदोलन केवल दलों में नहीं चल रहा है, इसकी आम कदम रज्यों में फैल चुकी है। ऐसी स्थिति में दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। ज्ञानेश कुमार को बचाने के चक्कर में जहां एक ओर सरकार के लिए चुनौतियां और परेशानी बढ़ रही है वहीं अब इसकी आंच न्यायापालिका

के ऊपर भी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के दो वर्ग आमने-सामने आ गए हैं। एक सीधे-सीधे मुन्य न्यायाधीश सूर्यकांत का इस्तीफा मांग रहा है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और एसआईआर को लेकर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वह लंबे समय से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की खंडपीठ में चल रही है। वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रही है। इसका आरोप अब सीधे-सीधे मुख्य न्यायाधीश पर लगाया जा रहा है, जिसके कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन सरकार के साथ-साथ अब न्यायापालिका के लिए भी चुनौती के रूप में देखने को मिल रही है। 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए थे।

एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन के तरीकों की सफलता मुख्यतया हानिकारक कीट एवं मित्र कीटों की निगरानी के आधार पर कीट प्रबंधन के विभिन्न घटकों के एकीकरण कर सही निर्णय को लागू करने के ऊपर निर्भर है।

फसल चक्र अपनाकर कीट नियंत्रण

किसी भी खेत में सब्जियों को लगाते समय उचित फसल-चक्र अपनाना चाहिए जिससे एक ही कुल की सब्जी को पुनः नहीं लगाना चाहिए। इस विधि से निरन्तर जीवन चक्र , अपेक्षाकृत संख्या एवं क्षति स्तर कम किया जा सकता है।

बुवाई व पौध रोपण के समय में परिवर्तन करके- कीटों के प्रति फसल की मुलायम अवस्था को ध्यान में रखकर फसल की बुवाई तथा रोपाई के समय में परिवर्तन करके अधिक हानि से बचाया जा सकता है। सब्जियों की बुवाई व रोपाई के समय में परिवर्तन कर लाल भुंग कीट, फल मक्खी, तना एवं फल छेदक कीट के प्रकोप को कम किया जा सकता है। पौधों की बुवाई व रोपाई ऐसे समय में करना चाहिए, जब पौधों की नाजुक अवस्थाएं एवं हानिकारक कीटों की निष्क्रिय अवस्थाएं समानान्तर हों।

सस्य क्रियाओं द्वारा कीट प्रबंधन

कीट प्रबंधन में इस घटक के ऊपर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता है, साथ ही यह पर्यावरण को सुरक्षित व अधिक टिकाऊ बनाता है। सस्य क्रियाओं का चयन ऐसा होना चाहिए जिससे नाशीकीटों के ऊपर एकीकृत एवं मित्र कीटों के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़े। इसके अन्तर्गत उचित किस्मों का चयन, बुवाई एवं रोपाई के समय में परिवर्तन, कीट-प्रपंच, फसल चक्र एवं अंतः फसलों का सही चुनाव आदि शामिल है।

अवरोधी एवं सहनशील किस्मों का उपयोग

किसी क्षेत्र के नाशीकीट एवं मित्र कीटों की विविधता एवं सघनता के आधार पर अवरोधी या सहनशील किस्मों का चुनाव समन्वित कीट प्रबंधन की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस प्रकार चयनित किस्मों में अपेक्षाकृत कीटों का प्रकोप कम होता है तथा रासायनिक दवाओं के उपयोग में भी कमी आती है। यह विधि सबसे सरल, सस्ती व दुष्प्रभाव रहित है।

ग्रीष्मकालीन जुताई

गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करके सुषुप्ता अवस्था में पड़े कीड़ों को नष्ट करना एक प्रभावी नियंत्रण विधि है। फसल की कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करके फल मक्खी, कद्दू का लाल भुंग तथा कटुआ कीट के जीवन चक्र को नष्ट कर उनकी सक्रियता को कम किया जा सकता है।

अन्तः फसलीकरण

सब्जियों की फसल के बीच में अन्तः फसलीकरण की



सब्जी उत्पादन में समन्वित कीट प्रबंधन

क्रिया के द्वारा भी कीटों के प्रकोप को कम किया जा सकता है। अन्तः फसलीकरण में लगाए गए भिन्न-भिन्न प्रकृति के पौधों द्वारा छोड़े जाने वाले जैव रसायन से कीटों के प्रौढ़ दूर भागते हैं तथा उनके द्वारा अण्डा देने की क्रिया भी कम हो जाती है। इस प्रकार के पौध रोपण प्रक्रिया से परभक्षी एवं परजीवी कीटों की क्रियाशीलता को बढ़ाती है। टमाटर एवं गोभी की अन्तः फसलीकरण से इन दोनों सब्जियों में कीट अकेले की अपेक्षा कम लगते हैं।

कीटों को आकर्षित करने वाली फसलों का उपयोग

मुख्य फसल के साथ ऐसी फसलों को लगाना चाहिए, जिनको कीट मुख्य फसल की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। आकर्षित करने वाली फसलों को मुख्य फसल में लगाकर बिना किसी रसायन के प्रयोग से मुख्य फसल को आसानी से कम लागत में उगाया जा सकता है। क्योंकि मुख्य फसल पर लगने वाले कीड़े आकर्षक फसलों पर आ जाते हैं, जिनको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। गोभीवर्गीय फसलों को हरी सूड़ी एवं पर्ण जालक कीट के नियंत्रण के लिए सरसों का तथा टमाटर में लगने वाली फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए गेंदे के फसल को आकर्षक फसल के रूप में प्रयोग करना चाहिए।

सब्जी में जैविक विधि से कीट नियंत्रण

समन्वित कीट प्रबंधन में जैविक नियंत्रण एक प्रमुख घटक है। किसी भी परिस्थिति में मित्र कीट एवं अन्य सूक्ष्म जीव मुख्यतया हानिकारक कीटों की संख्या को प्राकृतिक रूप से सीमित रखने में सहायता करते हैं। जैविक नियंत्रण

से इन्हीं कारकों का प्रभावी ढंग से समन्वित कीट प्रबंधन में प्रयोग होता है, तथा मित्र कीटों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारे परभक्षी व परजीवी कीट प्राकृतिक दशा में मित्र कीट के रूप में पाये जाते हैं, जो हानिकारक कीटों के विभिन्न अवस्थाओं को क्षति पहुंचाते हैं। एक हेक्टेयर टमाटर की फसल को फलछेदक कीट से रोकथाम के लिए 2,50,000 ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार क्राइसोपेरला कारनिया नामक परभक्षी कीट को 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से दस दिन के अन्तराल पर तीन बार छोड़ने से सफेद मक्खी, हरा फुदका, माहू आदि से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। कीटों के प्राकृतिक षत्रु को प्रयोगशाला में अधिक संख्या में उत्पादन कर, उसे सफलतापूर्वक, आवश्यकतानुसार फसलों पर छोड़कर विषैले रसायनों के उपयोग में कमी लायी जा सकती है।

त्यवहारिक नियंत्रण

इस विधि के अन्तर्गत प्रौढ़ कीटों को फेरोमोन का प्रयोग कर भ्रमित किया जाता है। सब्जियों में मुख्य रूप से बैगन का तना व फल बेधक, तम्बाकू की सूड़ी, टमाटर का फल बेधक एवं फल मक्खी को फेरोमोन द्वारा आकृष्ट कर नियंत्रण किया जा सकता है।

रसायनों का सुरक्षित एवं आवश्यक मात्रा का प्रयोग

रसायनों का अनियमित और अत्यधिक प्रयोग करने से कीटों में प्रतिरोधी क्षमता का विकास हो जाता है। साथ ही हानिकारक रासायनिक अवशेषों की वातावरण में वृद्धि होती है। समन्वित कीट प्रबंधन में यदि दूसरे कारकों के साथ सही संतुलन बनाकर सुरक्षित रसायनों की सही मात्रा एवं उचित अंतराल पर छिड़काव किया जाय तो कीटनाशी रसायन बहुत प्रभावी होता है। विभिन्न कीटनाशियों का अलग-अलग प्रतीक्षकाल होता है। इसलिए दवा छिड़कने के बाद प्रतिक्षकाल के बाद फल की तुड़ाई करने से रासायनिक अवयवों के अवषेध नहीं रहते हैं।

सूक्ष्म जीव द्वारा फसलों की सुरक्षा

सूक्ष्म जीव कीटनाशियों के अन्तर्गत जीवाणु, कवक और विषाणु का प्रयोग करके हानिकारक कीटों में रोग उत्पन्न कर उनका नियंत्रण किया जा सकता है। यह रोग हानिकारक कीड़ों में महामारी की तरह फैलता है जिससे कीड़े मर जाते हैं। सूक्ष्म कीटनाशियों में बी.टी. का प्रयोग व्यवहारिक स्तर पर किया जा रहा है। जिसके प्रयोग से गोभी का हिरक पृष्ठ कीट, भिण्डी का तना एवं फल छेदक कीट, टमाटर का फल बेधक कीटों का नियंत्रण संभव हुआ है।

यांत्रिक विधि से कीटों का नियंत्रण

कुछ कीट जिनको आसानी से देख जा सके उन्हें पकड़कर मार देना चाहिए। हड्डा बीटल, तम्बाकू की सूड़ी के अण्डे तथा तना व फल को भेदकर खाने वाली सूड़ी (बैगन व भिण्डी के फल छेदक कीट) को बहुत आसानी से देखकर कीट की विभिन्न अवस्थाओं को नष्ट कर देने से इनसे होने वाली क्षति से बचा जा सकता है। कीट नियंत्रण की इस विधि में लागत कम आती है एवं यह विधि सुरक्षित भी है।

सोयाबीन में बीमारी-कीट का नियंत्रण

बैक्टिरियल पस्क्यूल की समस्या होने पर कासुगेमेसिन 0.2 प्रतिशत, कॉपर आक्सीक्लोराइड 0.2 प्रतिशत, या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 पी.पी.एम. का छिड़काव करें।

गेरूआ रोग से बचाव के लिये हेक्जाकोनेजोल 5 ई.सी. या प्रोपाकोनेजोल 5 ई.सी. या ट्राईएडमिफान 25 डब्ल्यू. पी. या कापर आक्सीक्लोराइड 20 ई.सी. रोग के लक्षण दिखते ही तुरंत 0.1 प्रतिशत की दर से 40-45 दिन की फसल होने पर छिड़काव करें। इस छिड़काव से पौधे पूरी तरह भींगने चाहिए तथा 500-700 लीटर पानी प्रति हे. प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकतानुसार 15-20 दिन में छिड़काव दोहराना चाहिए।

कीट नियंत्रण

सोयाबीन फसल में कई कीटों का प्रकोप विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। इन कीटों में तने की मक्खी व चक्रभुंग (तना छेदक कीट), अर्ध कुन्डलक इल्ली, कम्बल कीट, तम्बाखू की इल्ली, अलसी की इल्ली, चने की फली छेदक (पत्ती भक्षक कीट), एवं सफेद मक्खी, जेसिडस माइट्स और थिप्स (रस चूसक) प्रमुख हैं।

इनके नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं

■ फेरोमोन ट्रैप लगाने से वयस्क कीट (उड़ने वाले) आकर्षित होकर ट्रैप में गिर जाते हैं जिससे इल्लियों जैसे कीटों का नियंत्रण संभव है।

■ तम्बाखू की इल्ली, एवं कम्बल कीट के नियंत्रण के लिये प्रभाविता पौधों से अंडगुच्छ एवं लावीगुच्छ वाली पत्तियों को एकत्र कर नष्ट कर दें। जब हम खेत का निरीक्षण करते हैं तब कागज की तरह या जालीदार पत्तियां जैसे ही दिखें वहां पत्तियों के नीचे अंड गुच्छ या लावीगुच्छ मिल जायेंगे, इस प्रकार की पत्तियों या पूरे पौधे को धीरे से इकट्ठा करें एवं बोरी में डालते जायें तथा अन्त में खेत से बाहर लाकर नष्ट कर दें। जिस जगह पर इस प्रकार की पत्तियाँ मिलें उसके चारों तरफ कीटनाशक का छिड़काव तुरंत करें।

तना छेदक मक्खी एवं सफेद मक्खी

फोरेट 10 जी. दानेदार दवा को 10 कि.ग्रा. प्रति हे. के हिसाब से जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। या थायामेथोक्जाम 70 डब्ल्यू. एस. 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बोनी पूर्व बीज उपचारित करें।

गर्दल बीटल (चक्रभृंग एवं पत्ती छेदक)

ट्रायजोफास 40 ई.सी. दवा 800 मि.ली. प्रति हे. के हिसाब से छिड़काव करें। या इंडोक्साकार्ब 14.5 एस.सी., 300 मि.ली. प्रति

छिड़काव करें।

पत्ती भक्षक कीट

स्पायनोसेड 45 एस.सी. 125 मि.ली. प्रति हे. या रायनेक्सीपीर 20 एस.सी. 100 मि.ली. प्रति हे. या क्लोरोपायरीफास 20 ई.सी. या क्यूनालफास 25 ई.सी. 1500 मि.ली. प्रति हे. या इंडोक्साकार्ब 15 ई.सी. 300 मि.ली. प्रति हे. के हिसाब से छिड़काव करें।

जेसिडस, एफिड, माइट्स

इथियान 50 ई.सी. दवा की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हे. के हिसाब से छिड़काव करें।

तना मक्खी एवं सफेद मक्खी

थायामेथोक्जाम 25 डब्ल्यू.जी.100 ग्राम प्रति हे. या इथोफेनप्रॉक्स 10 ई.सी. की 1 लीटर मात्रा प्रति हे. के हिसाब से छिड़काव करें।

जैविक कीटनाशक

■ बैक्टेरिया बेसियाना या बीटी, 1 लीटर प्रति हे. की दर से छिड़काव करने से पत्ती भक्षक इल्लियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

■ एच.ए.एन.पी.व्ही. या एस.आई.एन.पी.व्ही. की 250 एल.ई. प्रति हे. की दर से छिड़काव करने से भी पत्ती भक्षक कीटों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।



अरहर को कीट-रोग से बचाएं

कीट प्रबन्धन



चने की इल्ली: इल्लियाँ हरे से भूरे रंग की एवं शरीर के किनारों पर हल्की या गहरी लहरदार धारियाँ पाई जाती हैं। इसकी इल्लियाँ प्रारम्भिक अवस्था में पत्तियों को नुकसान पहुँचाती हैं तथा बाद की अवस्था में फल्ली में गोलाकार छेद बनाकर अपना सिर फल्ली में घुसाकर दाने को खाती हैं।

फल्ली मक्खी

इस कीट के वयस्क काले रंग के तथा आकार में घरेलू मक्खी से छोटे होते हैं। इसकी इल्लियाँ दाने में सुरंग बनाकर क्षति पहुँचाती हैं तथा क्षतिग्रस्त दानों में फफूंद का प्रकोप होने से यह खाने लायक नहीं रहती। क्षतिग्रस्त फल्लियाँ सूखकर सिकुड़ जाती हैं।

पोड बग

इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों फल्ली से रस चूसकर नुकसान पहुँचाते हैं, जिसमें फल्लियों में काले धब्बे बन जाते हैं। हरी फल्लियाँ गिर जाती हैं एवं फल्लियों में दाने सिकुड़े हुये, छोटे एवं कम संख्या में पाये जाते हैं।



रोग प्रबन्धन

उकटा (विल्ट)

यह रोग फ्यूजेरियम उडम नामक कवक द्वारा होता है। फसल में फूल एवं फल लगने की अवस्था में रोग का प्रकोप सर्वाधिक होता है। रोगी पौधा एकाएक पीला पड़कर सूखने लगता है।

रोकथाम के उपाय

रोग से बचने के लिये गर्मी में गहरी जुताई व निरोधक जातियाँ जैसे- सी.-11, जे.ए.-4, आशा, राजीव लोचन आदि लगाना चाहिये।

झुलसा रोग

इस रोग का प्रकोप, जहाँ पानी ठहरता है, वहाँ अधिक होता है। रोग के कारण पत्तियों पर पहले पीलीले धब्बे बनते हैं। कॉलर भाग में भूरे विशत बनते हैं। विशत भाग से पौधा टूट कर सूख जाता है। फसल को माद कूड़विधि से लगाये, बीज मादा में बोये। खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें। निंदाई- गुड़ाई समय पर अवश्य करें तथा अनावश्यक पौधे को निकाल दें ताकि उनका आवागमन अच्छा हो जिससे ज्यादा नमी न रहे। गमी की गहरी जुताई करें और संभव हो तो मिट्टी का सूर्यताप द्वारा मिट्टी का 6-7 सप्ताह के लिए निजीवीकृत करे ऐसा करने से मृदा जनित रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है।

ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें

चने की इल्ली व शंखी तेज धूप में मर जाती हैं तथा शिकारी पक्षियों द्वारा खा ली जाती हैं।

■ फसल की बोनी जून माह में करने से फल्लीभेदक कीटों के प्रकोप में कमी आती है।

■ ज्वार की अन्तर्वर्तीय फसल के रूप में तथा मक्का की ऊँची किस्म को खेत के बॉर्डर पर उगाएं। ये फसलें प्राकृतिक शत्रुओं के छिपने तथा शिकारी पक्षी उन पर बैठकर बड़ी संख्या में इल्लियों का भक्षण करते हैं।

■ गेंदा को ट्रैप फसल के रूप में बॉर्डर पर उगाएँ। इससे चने की इल्ली के प्रकोप में कमी आती है।

■ खेतों में चिड़ियों के बैठने हेतु 'ट्री' आकार की खूँटी 50 नग प्रति हेक्टेयर की दर से लगायें।

■ प्रकाश प्रपंच फसल से 10-15 मीटर की दूरी पर लगाएँ तथा सायं 6.30 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक चलाएँ।

■ चने की इल्ली की निगरानी के लिये पाँच फेरोमोन प्रपंच प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 30 दिनों बाद लगाएँ।

■ फसल की सतत् निगरानी करते रहें तथा कीटों का आर्थिक स्तर आने पर निम्नलिखित उपाय करें।

■ चने की इल्ली: 5 अण्डे या तीन छोटी इल्लियाँ/पौधा या 1 इल्ली/ 5 शाखाओं या 5-6 प्रौढ़/प्रपंच/दिन।

अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो 17-22 अक्टूबर तक उज्बेकिस्तान और भारत की यात्रा करेंगे, जामनगर का दौरा भी होगा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने के लिए अगले हफ्ते भारत के दौरे पर जाएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। रुबियो पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद जाएंगे और फिर 17-22 अक्टूबर तक भारत के मुंबई और जामनगर जाएंगे, ऐसा बताया गया। मई के बाद से यह रुबियो का दूसरा भारत दौरा होगा, जब उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर की होस्ट की गई व्हाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में हिस्सा लिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'वह अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, क्षेत्रीय और वैश्विक आयाम पर विचारों का आदान-प्रदान करने और बेहतर ऊर्जा सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे।' इसमें कहा गया है कि रुबियो व्यावसायिक निवेश और आर्थिक सहयोग के मोकों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे। रुबियो का जामनगर दौरा बहुत जरूरी है क्योंकि यह रिलायंस की रिफाइनरी का घर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-साइट फेसिलिटी है, जिसकी कैपेसिटी हर दिन 1.4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोसेस करने की है। मार्च में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि अमेरिका रिलायंस इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट से 50 साल में अपनी पहली रिफाइनरी बनाएगा।

फलाईरुबई मामले के बाद पाकिस्तान के पायलटों पर एक्शन, इजराइल जाने वाली फ्लाइट्स उड़ाने पर फ्रांस ने लगाई रोक

आबुधाबी, एजेंसी। एयर फ्रांस एयरलाइन ने पाकिस्तान के पायलटों और कैबिन क्रू (फ्लाइट स्टाफ) को इजराइल आने-जाने वाली फ्लाइट्स को उड़ाने या उनमें काम करने से मना कर दिया है। एयर फ्रांस उन नियमों का कड़ाई से पालन कर रही है, जिनके तहत जिन देशों के आपस में राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध नहीं हैं जैसे पाकिस्तान और इजराइल, उनके नागरिकों को उस रूट पर इयूटी नहीं दी जाएगी। अमेरिकी एयरलाइन यूनाइटेड एयरलाइंस और वेक एयरलाइन स्मार्टविंग्स ने भी इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रीयता के आधार पर लगाई गई पाबंदियां अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन संचालन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। इस सख्ती के पीछे की वजह 30 सितंबर, 2026 को दुबई से तेल अव्रीय जाने वाली फलाईरुबई की घटना को माना जा रहा है। फ्लाइट में ओमान के को-पायलट ने कॉकपिट में किए गए हमले के बाद बरती जा रही है। आरोप है कि को-पायलट ने फ्लाइट पर कंट्रोल करने की कोशिश में भारतीय कैप्टन पर हमला किया था। ओमान भी उन देशों की सूची में शामिल है, जिसके इजराइल देश के साथ कोई आधिकारिक या राजनीतिक संबंध नहीं है। फ्रांस के खोजी मीडिया संस्थान 'मीडियापाई' और एविशन इंटेलिजेंस कंपनी ने 13 अक्टूबर 2026 को अपनी रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी है। इन रिपोर्टों के अनुसार, एयर फ्रांस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने सभी पायलटों और कैबिन क्रू को इस रूट पर लगाए गए नए सुरक्षा प्रतिबंधों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है।

होर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के दो कटेनर जहाजों पर हमला, एक समुद्र में डूबा; सभी 43 क्रू मंबर सुरक्षित

सिंगापुर , एजेंसी। ईरान और अमेरिका के टकराव के कारण मध्य एशिया के लिए ऊर्जा का प्रमुख मार्ग होर्मुज स्ट्रेट संवेदनशील बना हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रही जहाज सुरक्षित नहीं है। इसी बीच इस मार्ग से गुजर रहे सिंगापुर में पड़ीकृत दो कटेनर जहाजों पर मंगलवार और बुधवार को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला किए जाने की खबर है। इस घटना में एक जहाज में आग लगने के बाद वह डूब गया, जबकि दूसरे जहाज को भी नुकसान पहुंचा। बुधवार को सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण ने यह जानकारी दी। सिंगापुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार जीएफएस प्राइड नामक जहाज हमले में क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई, जिसके बाद वह डूब गया। जहाज पर सवार सभी 21 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दूसरे जहाज जीएफएस गिजेल के बाहरी ढांचे को नुकसान पहुंचा। हालांकि, जहाज अपने इंजन की मदद से सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचने में सफल रहा। इस जहाज पर चालक दल के 22 सदस्य सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एम्पीए ने बताया कि दोनों जहाजों में कोई सिंगापुरी नागरिक सवार नहीं था।

ट्रंप की नई प्रेस सचिव की डिग्री पर उठे सवाल? खुद को लेकर कर रहीं वकील होने का दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सचिव केटी जकारिया इन दिनों अपनी योग्यता को लेकर विवादों में हैं। खुद को वकील बताने वाली जकारिया के पास कानून की डिग्री तो है, लेकिन अब तक ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, जिससे साबित हो कि उन्होंने अमेरिका के किसी राज्य में वकालत का लाइसेंस हासिल किया है। चीन की एक लॉ फर्म में काम करने के उनके दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं।

ट्रंप के सामने सवाल, जवाब अधूरा : मंगलवार को पहली बार प्रेस सचिव के तौर पर मीडिया के सामने आई जकारिया को अपने प्रदर्शन के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। इसके बाद पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि उन्होंने किस राज्य में वकालत की परीक्षा पास की है। ट्रंप ने जवाब देने के लिए जकारिया को आगे कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया, 'जब मैं चीन गई थी...' लेकिन मरीन वन हेलीकॉप्टर की आवाज के कारण उनकी बात पूरी तरह सुनाई नहीं दी। यह भी साफ नहीं हो सका कि वह आगे क्या कहना चाहती थीं।

डिग्री है, लेकिन लाइसेंस का रिकॉर्ड नहीं : जकारिया ने 2007 में पेपरडाइन यूनिवर्सिटी से स्नातक और 2011 में पेपरडाइन कार्सो स्कूल ऑफ लॉ से कानून की डिग्री हासिल की थी। हालांकि, कानून की



डिग्री होना और वकालत का लाइसेंस मिलना अलग-अलग बातें हैं। व्हाइट हाउस ने उनके बयान के हवाले से कहा कि उन्होंने सभी जरूरी योग्यताओं के साथ अंतरराष्ट्रीय को लेनदेन से जुड़े कानून के क्षेत्र में काम किया है। व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने भी उनका बचाव करते हुए उन्हें बेहद योग्य और तेज दिमाग वाला बताया।

चीन की लॉ फर्म में भी किया काम : जकारिया की लिंकडइन प्रोफाइल के मुताबिक, वह जून 2026 से ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप में वरिष्ठ संचार सलाहकार थीं। इससे पहले वह अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग में भी काम कर चुकी हैं। उनकी प्रोफाइल में

2011 से 2013 के बीच बीजिंग की झोंग लुन लॉ फर्म में अंतरराष्ट्रीय कानूनी मामलों से जुड़े काम का जिक्र है। इसके अलावा, वह क्वासी मजदूरों के बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन और कैलिफोर्निया के एक राजनीतिक संगठन से भी जुड़ी रही हैं। उनके पुराने परिचय में विश्व बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह देने के अनुभव का भी दावा किया गया है।

50 राज्यों में नहीं मिला लाइसेंस का रिकॉर्ड : कैलिफोर्निया स्टेट बार के प्रवक्ता के मुताबिक, संस्था के पास केट शेरान जकारिया या केट शेरान ब्लैक नाम से वकालत का लाइसेंस होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्वतंत्र मीडिया संस्थान पॉपुलर इन्फॉर्मेशन ने भी दावा किया कि अमेरिका के सभी 50 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में उनके लाइसेंस का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद गिंगरानी संगठन कैपेन फॉर अकाउंटैबिलिटी ने कैलिफोर्निया स्टेट बार में शिकायत देकर मामले की जांच की मांग की। संगठन का कहना है कि बिना लाइसेंस के खुद को वकील बताना कानून का उल्लंघन हो सकता है।

फिलहाल, स्टेट बार ने गोपनीयता नियमों का हवाला देते हुए शिकायत या जांच की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में जकारिया की पेशेवर योग्यता पर विवाद बना हुआ है।

अमेरिका ने यूक्रेन को मझाघार में छोड़ा?: जेलेंस्की ने ट्रंप के सलाहकारों पर उठाए सवाल

लंदन, एजेंसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को रूस के साथ डीलज आर्पुटि समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी ईथन आयात करने पर सहमत होकर वाशिंगटन ने गलत पथ चुना है। उन्होंने ट्रंप से गैररको के खिलाफ युद्ध में कीव का समर्थन करने की अपील की। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, ब्रिटिश शो 'प्रियर्स ऑनल अनलैसर्ड' पर जेलेंस्की ने कहा, 'जब राष्ट्रपति ट्रंप हमारा पक्ष नहीं, बल्कि किसी एक पक्ष का साथ देते हैं, तो यह दुःखद होता है। लेकिन हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि वह कीव का रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन अगर आप कीव का रास्ता अपनाते हैं तो आपको कीव में ही रहना होगा। गलत पक्ष में नहीं।' जेलेंस्की ने इस गुटे ट्रंप को मिल रही सलाह पर भी सवाल उठाया और कहा, 'मुझे लगता है कि उनके सलाहकार गलत हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कौन उम्मीद रख है। सही पक्ष की ओर नहीं, यह इतिहास का सही पक्ष नहीं है।' साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा कि इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि यूक्रेन एक महत्वपूर्ण संयोजी का समर्थन खो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक समझौते की घोषणा के बाद आई है।

अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम: दूतावास ने पुलिस की तारीफ



एलेक्जेंड्रिया पैपेराकिस को एक हिंदू मंदिर में संभावित सामूहिक गोलीबारी की धमकियों की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जांच 11 अक्टूबर को शुरू हुई, जब माउंट प्रॉस्पेक्ट पुलिस विभाग ने पैलेटाइन पुलिस विभाग को एक हिंदू मंदिर में संभावित सामूहिक गोलीबारी की जानकारी दी। यह जानकारी एक व्यक्ति से मिली थी, जिसने बताया

शिकागो, एजेंसी। शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने बुधवार को अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की। यह कार्रवाई इलिनोइस में हिंदुओं के एक पूजा स्थल को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर गोलीबारी की साजिश रचने के आरोपी 19 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी के बाद की गई थी।

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने क्या कहा : शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा, 'उसे इलिनोइस के ऑरेंगो में एक पूजा स्थल को निशाना बनाने की कथित नाकाम कोशिश से जुड़ी खबरों की जानकारी है। दूतावास ने पुष्टि की कि वह इस मामले पर करीबी नजर रख रहा है और भारतीय समुदाय के लोगों के संर्पर्क में है। पैलेटाइन पुलिस विभाग के अनुसार, 19 वर्षीय संदिग्ध

पिछले एक दशक में भारत-यूआई साझेदारी इस बात का बेहदरीन उदाहरण है कि कैसे दोनों देशों ने बदलते वैश्विक माहौल के अनुसार खुद को ढाला है। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। ईरान में जारी संघर्ष और यमन में हूती समूह तथा सऊदी अरब के बीच बढ़े तनाव ने क्षेत्र की स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। इस बीच, रविवार को दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने जानकारी दी कि 'एमटी जेम नंबर 2' नामक कच्चे तेल के टैंकर में हुए हादसे के बाद 22 भारतीय चालक दल के सदस्यों को रस अल खैमाह तट के पास सुरक्षित बना लिया गया। वाणिज्य दूतावास ने 'एक्स' पर कहा, 'हमें 'एमटी जेम नंबर 2' जहाज से जुड़े हादसे की जानकारी मिली, जिसमें 22 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे।

उन्होंने इसकी सूचना संगठन को नहीं दी थी। मई में एक जज ने दो मुकदमों से सेफस्पोट को बाहर कर दिया। अदालत ने माना कि संघीय कानून के तहत संगठन को कानूनी संरक्षण प्राप्त था। गार्डनर, यूएसए जिम्नास्टिक्स और चाउज जिम्नास्टिक्स के खिलाफ कई मुकदमे अभी चल रहे हैं। 90 साल की सजा से इस मामले में अहम फैसला जरूर आया है, लेकिन पीडिताओं के आरोपों और खेल संस्थानों की जवाबदेही से जुड़े सवाल अभी बाकी हैं। यह मामला बताता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए शिकायतों को गंभीरता से लेना और समय रहते कार्रवाई करना कितना जरूरी है।

उन्होंने इसकी सूचना संगठन को नहीं दी थी। मई में एक जज ने दो मुकदमों से सेफस्पोट को बाहर कर दिया। अदालत ने माना कि संघीय कानून के तहत संगठन को कानूनी संरक्षण प्राप्त था। गार्डनर, यूएसए जिम्नास्टिक्स और चाउज जिम्नास्टिक्स के खिलाफ कई मुकदमे अभी चल रहे हैं। 90 साल की सजा से इस मामले में अहम फैसला जरूर आया है, लेकिन पीडिताओं के आरोपों और खेल संस्थानों की जवाबदेही से जुड़े सवाल अभी बाकी हैं। यह मामला बताता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए शिकायतों को गंभीरता से लेना और समय रहते कार्रवाई करना कितना जरूरी है।

ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होगा, ऊर्जा कीमतों में तेजी से आएगी गिरावट', ट्रंप का नया दावा

वाशिंगटन , एजेंसी। एरिजोना से मोंटाना में एक चुनावी रैली के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उनका दावा है कि युद्ध खत्म होने के बाद तेल और ऊर्जा की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था। यह युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इससे पहले एरिजोना के बुलहेड सिटी में आयोजित एक चुनावी रैली में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और उसके अस्पर पर विस्तार से बात की। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने

ईरान की सैन्य ताकत को काफी कमजोर कर दिया है, जिसमें उसकी नौसेना और वायुसेना की क्षमताएं भी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि? सैन्य कार्रवाई इतनी व्यापक रही कि अब अमेरिका के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि बातचीत किस ईरानी अधिकारी से की जाए। उन्होंने कहा, 'शायद मैं बहुत आगे निकल गया। मुझे नहीं पता कि आखिर बात किससे करनी है।' यह टिप्पणी उन्होंने ईरानी नेतृत्व के कई स्तरों को हटाने के संदर्भ में की। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जिसके जरिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस दुनिया भर में भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि हमने होर्मुज स्ट्रेट पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है और इस समय वहां से पहले की तुलना में अधिक तेल बाहर जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक, यह स्थिति अमेरिकी नौसैनिक अभियानों की वजह से संभव हुई है। उन्होंने इन अभियानों को 'स्टील की दीवार' जैसा बताया।

जयशंकर ने यूआई के विदेश मंत्री अल-नाहयान से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा



में अब्दुल्ला बिन जयद अल नाहयान के साथ हिस्सा लिया। नाहयान यूआई के उप प्रधानमंत्री भी हैं। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और बहुपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। जयशंकर ने 'एक्स' पर कहा कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि दुनिया की व्यवस्था तेजी से बदल रही है। यह बदलाव लंबे समय से चल रहे रुझानों और कई घटनाओं, दोनों का नतीजा है। उन्होंने कहा, 'हर देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसी वजह से नए साझेदारों और नए विकल्पों की तलाश स्वाभाविक है।' जयशंकर ने कहा कि आज की साझेदारियां पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर अधिक रणनीतिक समझ विकसित करने की मांग करती हैं। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है और इसे छोटे लंबे समय से चल रहे रुझानों और जरिए समर्थन दिया जा सकता है।

दिया है। कुछ पूर्व छत्राओं के वकीलों का आरोप है कि यूएसए जिम्नास्टिक्स और अमेरिकी सेंटर फॉर सेफस्पोट को 2017 में ही गार्डनर के अनुचित व्यवहार की जानकारी मिल गई थी, लेकिन उसे खेल से बाहर करने में देरी हुई। शिकायत के बाद 2022 में हुई कार्रवाई : सेफस्पोट ने 2022 में यौन शोषण की शिकायत मिलने के बाद गार्डनर को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इसी साल चाउज जिम्नास्टिक्स ने भी उसे नौकरी से निकाल दिया। सेफस्पोट की जांच में सामने आया कि चाउ और कुछ अन्य कोचों को गार्डनर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोपों की जानकारी थी, लेकिन

पर उठे सवाल : गार्डनर मसाहूर कोच लियांग 'चाउ' चियाओ के संस्थान में काम करता था। वह युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ आयोवा में आयोजित होने वाली एक बड़ी वार्षिक प्रतियोगिता का निदेशक भी था। ऐसे में उसके खिलाफ लगे आरोपों ने अमेरिकी जिम्नास्टिक्स जगत को झकझोर

अमेरिका: फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगेगी रोक? अदालत से कानून को मंजूरी

फ्लोरिडा , एजेंसी। फ्लोरिडा राज्य को बुधवार को अदालत में एक अहम जीत मिली है। इस फैसले के बाद, राज्य अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने और अन्य पाबंदियां लागू करने में सक्षम होगा। 2024 में जब गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे, तब यह बच्चों की सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका के सबसे सख्त कानूनों में से एक था। अपील अदालत ने कहा कि यह कानून 'फर्स्ट अमेंडमेंट' (अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन) से जुड़ा है, लेकिन संभवतः यह किसी खास कंटेंट के बजाय तटस्थ तरीके से लागू होता है। 11वें अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की एक बेंच ने 3-0 के बहुमत से कहा कि यह कानून कानूनी चुनौतियों में टिक सकता है, क्योंकि यह बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए जरूरी हद से ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाता है।' यह कानून फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगाता है। वहीं, 14 या 15 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के वास्ते माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। 'कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन' और 'नेटचॉइस' जैसे इंडस्ट्री समूहों ने फ्लोरिडा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका तर्क था कि

यह कानून सोशल मीडिया कंपनियों और उपयोगकर्ताओं के 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के अधिकारों का उल्लंघन करता है। 2025 में एक जज ने कहा था कि यह कानून संभवतः असंवैधानिक है और इस पर रोक (इंजंक्शन) लगा दी थी। जब अपील अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी, तब उस रोक को होल्ड पर रखा गया था। अब यह रोक हटा दी गई है। वहीं, यह मुकदमा वापस तहसील की फेडरल कोर्ट में जाएगा। अपील अदालत ने बताया कि यह कानून उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होता है, जिनके बारे में यह तय किया गया है कि वे बच्चों को सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही, यह केवल उन्हीं प्लेटफॉर्म पर लागू होता है जो एल्गोरिदम और लत लगाने वाले कई फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरिडा के अर्टोनी जनरल के कार्यालय से टिप्पणी मांगने के लिए जरूरी हद से ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाता है।' यह कानून फ्लोरिडा में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगाता है। वहीं, 14 या 15 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के वास्ते माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। 'कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन' और 'नेटचॉइस' जैसे इंडस्ट्री समूहों ने फ्लोरिडा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका तर्क था कि

अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम: दूतावास ने पुलिस की तारीफ

एलेक्जेंड्रिया पैपेराकिस को एक हिंदू मंदिर में संभावित सामूहिक गोलीबारी की धमकियों की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जांच 11 अक्टूबर को शुरू हुई, जब माउंट प्रॉस्पेक्ट पुलिस विभाग ने पैलेटाइन पुलिस विभाग को एक हिंदू मंदिर में संभावित सामूहिक गोलीबारी की जानकारी दी। यह जानकारी एक व्यक्ति से मिली थी, जिसने बताया

यूक्रेन में स्टारलिक पर पाबंदी से घिरे मस्क: रूस के हमलों के बीच उठे सवाल

कीव, एजेंसी। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में स्टैलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिक को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया है, जिसने दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल एलन मस्क को कटघरे में ला खड़ा किया है। आरोप है कि यूक्रेन में इस सेवा पर लगी पाबंदियों से यूक्रेनी सेना के संचार और सैन्य अभियानों पर असर पड़ा है। अमेरिकी सांसदों ने भी इस कदम पर सवाल उठाए हैं। अब बक्स सिर्फ इंटरनेट सेवा की नहीं, बल्कि इस बात की है कि क्या कोई निजी कंपनी युद्ध के दौरान किसी देश की रक्षा क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

स्टारलिक बंद होने से क्या मचा बवाल : यूक्रेन की सेना युद्ध के दौरान स्टारलिक पर काफी हद तक निर्भर है। इसका इस्तेमाल ड्रोन उड़ाने, खुफिया जानकारी जुटाने और सैनिकों के बीच संपर्क बनाए रखने में किया जाता है। ऐसे में कनेक्टिविटी में रुकावट आने से मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई गई। अमेरिकी सांसदों ने आरोप लगाया कि रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन की संचार सेवाओं पर रोक लगाना बेहद गंभीर मामला है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के डेमोक्रेटिक सदस्यों ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि इस तरह की पाबंदियां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फायदा पहुंचा सकती हैं। वहीं, सेंसद प्रभिला जयपाल ने चेतावनी दी कि किसी एक कंपनी के पास युद्ध के दौरान संचार व्यवस्था रोकने की ताकत होना खतरनाक मिसाल बन सकता है। जेलेंस्की ने मस्क पर उठाए सवाल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर

तस्वीरों भी साझा की थीं। पैपेराकिस को उसके घर से निकलते समय ढूंढ निकाला गया और हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद, पैलेटाइन पुलिस के जासूसों ने उसके घर की तलाशी ली। बरामद की गई वस्तुओं में बाँडी आर्मर से लैस एक सामरिक जैकेट और श्वेत वर्चस्ववादी उग्रवाद से जुड़े प्रतीकों वाला एक पैच शामिल था। इसमें श्वेत वर्चस्ववादी और चरमपंथी विचारों से जुड़े बयान होने की बात कही गई है। दस्तावेज में भारतीय मूल के लोगों सहित दक्षिण एशियाई समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा की भी जिक्र था। जांच एजेंसियां अब इन दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक बातचीत और बरामद सामान की पड़ताल कर रही हैं, ताकि कथित साजिश के उद्देश्य और उसकी तैयारी से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाई जा सके।

यूक्रेन में स्टारलिक पर पाबंदी से घिरे मस्क: रूस के हमलों के बीच उठे सवाल



जेलेंस्की ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई। ब्रिटिश पत्रकार पियर्स मॉर्गन के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि रात करीब एक बजे स्टारलिक की सेवाएं रोक दी गई थीं। उनके मुताबिक, इसका असर यूक्रेन की सैन्य गतिविधियों और रूसी हमलों से बचाव की कोशिशों पर पड़ा। जेलेंस्की ने कहा कि यह सेवा काफी दुरमन पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने आशंका जताई कि संचार व्यवस्था में बाधा आने से रूसी हमलों को रोकने में मुश्किल हुई और लोगों की जान जाने का खतरा बढ़ा। उन्होंने मस्क के फैसले को बड़ी गलती बताया। मस्क ने स्टारलिक और स्टारशील्ड में बताया अंतर विवाद बढ़ने पर एलन मस्क ने सफाई देते हुए स्टारलिक और स्टारशील्ड को अलग-अलग सेवाएं बताया। उनके अनुसार, स्टारलिक स्पेसएक्स की व्यावसायिक सेवा है, जिसका इस्तेमाल नागरिक और रक्षात्मक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। मस्क का कहना है कि व्यावसायिक सेवा का इस्तेमाल आक्रामक सैन्य कार्रवाई के लिए करना उचित नहीं होगा। वहीं, स्टारशील्ड अमेरिकी सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली सैन्य संचार प्रणाली है।

